भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस का संपादित पाठ
7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि:
श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री स्वामिनाथन जे - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. पूनम गुप्ता - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री शिरीष चंद्र मुर्मू - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री रोहित जैन - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री संजय कुमार हंसदा – कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री इंद्रनील भट्टाचार्य - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री रवि शंकर - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

मॉडरेटर:

श्री ब्रिज राज - भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक

ब्रिज राज:

सभी को शुभ मध्याह्न। मौद्रिक नीति के बाद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चौथी है। हमारे साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा; उप गवर्नर श्री स्वामिनाथन जे; डॉ. पूनम गुप्ता; श्री शिरीष चंद्र मुर्मू; और श्री रोहित जैन हैं। हमारे साथ कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार हंसदा; श्री इंद्रनील भट्टाचार्य; और श्री रवि शंकर भी हैं। मैं रिज़र्व बैंक के अन्य सदस्यों का भी स्वागत करता हूं।

सर, मीडिया से 26 प्रतिभागी हैं। शुरू करने से पहले, मैं दो घोषणाएं करना चाहूंगा। पहली, मैं मीडिया प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया केवल एक प्रश्न पूछें। मैं दोहराता हूं, केवल एक प्रश्न, ताकि सभी को मौका मिले। दूसरी, बोलते समय कृपया माइक्रोफोन ऑन करें ताकि लाइव टेलीकास्ट देखने वाले स्पष्ट रूप से सुन सकें। जब आप बोलना समाप्त कर लें, तो कृपया माइक्रोफोन बंद कर दें।

सर, आपकी अनुमति से, मैं अब नाम बुलाऊंगा।

संजय मल्होत्रा:

हां, चलिए शुरू करते हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं सीएनबीसी टीवी18 से श्रीमती लता वेंकटेश को अपना पहला प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। लता, कृपया।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी टीवी18:

बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नर और आरबीआई को धन्यवाद। सर, आपने अपने भाषण में बताया कि अगले तीन तिमाहियों में मुद्रास्फीति का औसत 5.8% है। अब, इसका अर्थ है कि वास्तविक दर के संदर्भ में यह अभी भी एक बहुत ढीली नीति है। क्या आप सभी ने 50 आधार अंक की वृद्धि पर विचार किया था? पिछली एमपीसी बैठक के मिनट्स के अनुसार, आपने कहा था कि आप मुद्रास्फीति सामान्य होने पर नीति को पुनर्परिकलित करेंगे। क्या हमें आगामी नीतियों में वास्तविक दर के पुनर्परिकलन की उम्मीद करनी चाहिए?

संजय मल्होत्रा:

तो, इसी प्रश्न के दो भाग हैं, है ना? एक यह कि क्या आपने 50 आधार अंक दर में वृद्धि पर विचार किया? तो, हम सभी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं और फिर विचार करते हैं कि कौन- सा उपयुक्त मौद्रिक नीति निर्णय होगा।

वास्तविक दर के संबंध में, ज़ाहिर है, इसका पुनर्परिकलन, यहां तक कि 25 आधार बिंदु की वृद्धि भी दर को पुनर्परिकलित करती है। मैं मानता हूं कि आपका प्रश्न यह है कि अधिक आवश्यक है या नहीं, यह एक निर्णय है जो लिया जाएगा। जैसा कि हमने कहा है, आगे चलकर, यह एमपीसी पर निर्भर होगा कि वह इसे कैसे लेता है।

लेकिन ज़ाहिर है, नीति का रुख बदलकर हमने स्पष्ट किया है कि भविष्य में दर कटौती नहीं है। हम या तो ठहराव या फिर दरों में बढ़ोतरी के बारे में सोच रहे हैं। दर वृद्धि कितनी गहरी या कितनी कम होगी, यह विकसित होती समष्टि आर्थिक स्थितियों और संवृद्धि -मुद्रास्फीति गतिशीलता पर निर्भर करेगा।

केवल हेडलाइन पर विचार करने से, जैसा कि हमने बताया है, जबकि हेडलाइन हमें सरकार द्वारा दिया गया लक्ष्य है, और हम हेडलाइन को 4% के लक्ष्य तक लाने की कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन यह एकमात्र चीज नहीं है जिसे देखा जाना चाहिए। जैसा कि हमने कहा है, अंतर्निहित मुद्रास्फीति, वह मार्ग जहां यह जा रही है, खासकर इन समयों में जब हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा, एक, आधार प्रभाव और अन्य आपूर्ति-पक्ष के कारकों के कारण है। इसलिए, हेडलाइन अकेले सही मापदंड नहीं हो सकता है, और इसलिए हमें अन्य मापदंडों को देखना होगा जो हमने दिए हैं, जैसे कि मूल, प्रसार सूचकांक, आदि, ताकि हम एक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें, ताकि हम अंतर्निहित मुद्रास्फीति को समझ सकें और यह देख सकें कि यह कहां जा रही है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। सर, हम बायीं तरफ से कुछ और प्रश्न लेंगे और फिर इस तरफ आएंगे। मैं अब बिजनेस स्टैंडर्ड से मनोजित साहा को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। मनोजित, कृपया।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

धन्यवाद, सर। ऋण वृद्धि बहुत मजबूत रही है। यह लगभग 19% दर है। इस दर वृद्धि के साथ और, जैसा कि आपने कहा है कि आगे चलकर, दर कटौती नहीं होगी, या तो ठहराव होगा या दर वृद्धि, तो ब्याज दरें समग्र रूप से, सामान्य रूप से, सख्त हो जाएंगी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऋण वृद्धि यहां से थोड़ी कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी? और यदि आप चलनिधि की स्थिति के बारे में भी बता सकते हैं क्योंकि मूल चलनिधि अभी भी ₹10 ट्रिलियन है, मुझे लगता है।

संजय मल्होत्रा:

मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा।

मनोजित साहा:

ठीक है।

संजय मल्होत्रा:

और मैं आपका दूसरा प्रश्न उत्तर दूंगा यदि अन्य लोग उसी प्रश्न को नहीं पूछते हैं। मुझे यकीन है कि यह आएगा। आपका पहला प्रश्न ऋण वृद्धि पर - जैसा कि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उल्लेख किया था, यह सभी समय के उच्चतम स्तर पर है, मुझे लगता है, पिछले आंकड़ों के आधार पर, 19% वृद्धि दर सबसे अधिक में से एक है। और यह कई कारणों से है। क्या यह आगे चलकर कम होगा? मुझे लगता है कि यह मजबूत बना रहेगा। यहां- वहां कुछ प्रतिशत बिंदु वास्तव में समग्र दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन यह जारी रहेगा और संवृद्धि का समर्थन करेगा।

मनोजित साहा:

धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं ब्लूमबर्ग से अनुप रॉय को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। अनुप, कृपया।

अनुप रॉय, ब्लूमबर्ग:

धन्यवाद, सर। सर, आपने आज अपने वक्तव्य में वैश्विक कारकों के बारे में उल्लेख किया। अब, वैश्विक कारक, जैसे यूएस फेड नीति आदि, आरबीआई नीति निर्णय पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं? या यह अभी भी घरेलू कारकों पर बहुत अधिक केंद्रित है?

संजय मल्होत्रा:

नहीं, मुख्य रूप से, हमारे नीति निर्णय घरेलू संवृद्धि और मुद्रास्फीति और समष्टि आर्थिक स्थितियों और संभावना पर आधारित हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि बाहरी बल, स्थितियां, मायने नहीं रखती हैं। वे मायने रखते हैं। वे हमारी संवृद्धि, मुद्रास्फीति और हमारी ब्याज दरों को प्रभावित करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले साक्षात्कार में उल्लेख किया था। और इस पर चर्चा की जाती है और इसका मिनट्स में भी उल्लेख किया जाता है, हमेशा। इसलिए, वे हमारे मौद्रिक नीति निर्णयों में ध्यान में रखे जाते हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मनीकंट्रोल से हंसिनी कार्थिक को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। हंसिनी, कृपया।

हंसिनी कार्थिक, मनीकंट्रोल:

धन्यवाद। शुभ मध्याह्न, सभी। सर, मेरा प्रश्न वर्तमान में प्रणाली में उपलब्ध चलनिधि के बारे में है। हर बार जब प्रणाली में चलनिधि का बहाव होता है, तब एनबीएफसी ऋण के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर थोड़ी सी आस्ति गुणवत्ता की समस्या हो रही है। अब एक तरफ, आरबीआई परिक्रामी ऋण को एक उत्पाद के रूप में प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ महत्वपूर्ण ऋण पॉकेट में सूखे की स्थिति भी उभर रही है। आप उच्च चलनिधि और परिक्रामी ऋण के कम होने के परिदृश्य को कैसे देखते हैं? क्या आप आश्वस्त है कि ऐसी ही स्थिति हमें संपत्ति गुणवत्ता समस्याओं के लिए नहीं होगी?

संजय मल्होत्रा:

हां, मेरा मतलब है एनबीएफसी वृद्धि दर बहुत मजबूत रही है, बैंकों द्वारा एनबीएफसी को ऋण वृद्धि लगभग 37% है, और एनबीएफसी ऋण वृद्धि स्वयं भी बहुत मजबूत है। समग्र रूप से, मुझे लगता है कि यह बैंकों की तुलना में कम है। हमें जांच करनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह कम है। एनबीएफसी द्वारा वास्तविक अर्थव्यवस्था को ऋण बैंकों की तुलना में कम है।

हम एनबीएफसी के संबंध में आस्ति गुणवत्ता से संबंधित कोई मुद्दे या चिंताएं नहीं देखते हैं। हम ऐसे जोखिमों के प्रति हमेशा सतर्क रहते हैं, न केवल आस्ति गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, बल्कि एमपीसी द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार, बनने वाले मांग और मूल्य दबाव पर भी। इसलिए, हम ऐसे जोखिमों के प्रति सचेत हैं, लेकिन हमें अभी तक ऐसे जोखिमों के उत्पन्न होने का अनुभव नहीं हुआ है।

हंसिनी कार्थिक:

धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं ज़ी बिजनेस से एकता सूरी को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। एकता, कृपया।

एकता सूरी, ज़ी बिजनेस:

शुभ मध्याह्न, सर। सर, मेरा प्रश्न हंसिनी के प्रश्न पर थोड़ा फॉलो-अप वाला है। यदि एनबीएफसी में कोई आस्ति गुणवत्ता समस्या नहीं है, तो परिक्रामी ऋण के लिए मांग के संबंध में वे तर्क देते हैं कि वे अंतिम मील तक पहुंचे, तो क्या मीयादी ऋण के साथ कुछ छूट दी जा सकती है? या क्या आरबीआई अनिवार्य रूप से एनबीएफसी को बता रहा है कि यह नियम नहीं है, आपने यह क्यों शुरू किया, और क्या मसौदा निदेश उन्हें याद दिलाने के लिए थे?

संजय मल्होत्रा:

आपने प्रश्न पूछा और उत्तर भी दे दिया। मुख्य रूप से, जैसा कि आपने कहा, हमने प्रकाशित किए गए मसौदा विनियमन एक तरह से स्पष्टीकरण हैं। यह एक नया नियम या विनियम नहीं है क्योंकि एनबीएफसी को परिक्रामी ऋण प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। यह केवल एक स्पष्टीकरण नहीं है; आरबीआई के पर्यवेक्षण के दौरान इस संबंध में निदेश कई बार प्रत्येक एनबीएफसी को दिए गए थे।

अब, तकनीकी प्रगति के कारण, सॉफ्टवेयर और तकनीक का उपयोग करके, परिक्रामी ऋण एक मीयादी ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसलिए, इन्हें विनियमन में शामिल करने के लिए, हमने मसौदा निदेश प्रकाशित किए हैं। हमें इसके बारे में कई टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी हम समीक्षा कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा, हम इसे पुहह देखेंगे, अपना दृष्टिकोण बनाएंगे, और जल्द ही एक अंतिम निर्णय लेंगे, यह ध्यान में रखते हुए कि क्या यह कोई प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें चलनिधि जोखिम हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह पहले से ही अनुमत नहीं था। अब, क्या ऐसी स्थितियां अभी भी मौजूद हैं या नहीं, इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम आगे की दिशा के बारे में निर्णय लेंगे।

एकता सूरी:

सर, बदलते समय के साथ, क्या आरबीआई इस पर अपना दृष्टिकोण थोड़ा बदल सकता है?

संजय मल्होत्रा:

आप आगे चलकर यह जान लेंगे। जब हम इसे जल्द ही अंतिम रूप देंगे, तो आप जान लेंगे। अभी इसकी जांच चल रही है। मेरे स्तर पर इस पर पूर्ण चर्चा नहीं हुई है। विभाग ने इसका परीक्षण किया है, इसका अध्ययन किया है, इसका विश्लेषण किया है। अब वे इसे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। सभी डीजी, गवर्नर, हम एक साथ बैठकर एक सामूहिक निर्णय लेंगे। आप इसके बारे में जल्द ही जान लेंगे।

एकता सूरी:

धन्यवाद, सर।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं ईटी नाउ स्वदेश से अनुराग शाह को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। अनुराग, कृपया।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:

धन्यवाद, सर। सर, एफसीएनआर जमा योजना को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। आरबीआई इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानता है? और बैंकों से आरबीआई की अपेक्षाएं क्या होंगी, चूंकि चलनिधि बैंकों तक पहुंच गई है और मार्जिन भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकते हैं? तो, आरबीआई की किस प्रकार की अपेक्षाएं होंगी? सर, कुछ बुद्धिजीवी यह भी मानते हैं कि भविष्य में, यदि पुनर्भुगतान के समय रुपया कमजोर हो जाता है, तो इसका खजाने पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें इसे कैसे देखना चाहिए?

संजय मल्होत्रा:

सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि लगभग 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफसीएनआर (बी) के साथ ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि, हमारे देश की समष्टिआर्थिक मूलभूत सुविधाओं और हमारी अर्थव्यवस्था की शक्ति को प्रतिबिंबित करती है। इतने कम समय में और इतने बड़ी मात्रा में, हमने ये जमा प्राप्त किए हैं, जो लगभग 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है।

बैंकों के संबंध में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बैंक इन जमा का उपयोग सावधानीपूर्वक करेंगे, विचार करके, जैसा कि उन्होंने पिछले समय में किया है और भविष्य में भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋण में निश्चित रूप से 19% की वृद्धि हुई है। हमारे पास ऋण की बहुत अधिक आवश्यकता और जरूरत है, इसलिए यह एक अपूर्ण मांग को पूरा कर रहा है। बैंक इसे सावधानीपूर्वक करना जारी रखेंगे; यह हमारा उन पर विश्वास है।

जंहा तक भुगतान के प्रश्न का संबंध है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी समष्टिआर्थिक मूलभूत सुविधाएं बहुत मजबूत हैं। यह बाहरी चुनौतियों के कारण एक अस्थायी गतिविधि है, जिसने प्रवाह में थोड़ी गिरावट

लाई है और हमारे चालू खाते पर कुछ दबाव डाला है। यह एक अस्थायी मुद्दा है, और जल्द ही, हमारा बाहरी क्षेत्र यहां से और भी मजबूत हो जाएगा।

हमें इसके सभी संकेत मिल रहे हैं, चाहे वह सकल एफडीआई, सेवा निर्यात, विप्रेषण हों, या भारत सरकार द्वारा सुधार, कारोबार में आसानी, बीमा और अन्य क्षेत्रों में एफडीआई का विस्तार, या सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित कर संबंधी और अन्य उपायों को तार्किक बनाना हो।

इन सभी के कारण, हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही हमारा बीओपी, जो वर्तमान में घाटे में है, पिछले वर्षों की तरह अधिशेष में चला जाएगा। हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं, जिन पर भरोसा करके हम इसका पुनःभुगतान करेंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। सर, अब हम कुछ प्रश्न दाईं ओर से लेंगे। मैं इकॉनॉमिक टाइम्स से संगीता मेहता को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। संगीता, कृपया।

संगीता मेहता, इकॉनॉमिक टाइम्स:

धन्यवाद। सर, पॉलिसी के बाद की प्रतिक्रियाओं में, कुछ बड़े बैंकों ने कहा है कि वे अगले 2 से 3 महीनों तक जमा दरों में वृद्धि नहीं करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि उनके पास अधिशेष एफसीएनआर (बी) जमा हैं। मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप कब तक बैंकों से जमा पक्ष पर संचरण होने की उम्मीद करते हैं? और एक संबंधित प्रश्न है कि आप कब तक बैंकों से एफसीएनआर (बी) जमा का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं?

संजय मल्होत्रा:

हम पहले से ही एफसीएनआर (बी) जमा के उपयोग को देख रहे हैं, जैसा कि उच्च वृद्धि दर से साबित होता है। लेकिन निश्चित रूप से, राशि इतनी बड़ी है, हम नहीं चाहते कि वे उन्हें एक ही रात में उपयोग करें। उन्हें पूरी तरह से जांच-पड़ताल करनी चाहिए और इन जमा राशियों का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त समय लेना चाहिए।

चलनिधि के संबंध में, आज अधिशेष चलनिधि है, जो आवश्यक चलनिधि से बहुत अधिक है, लेकिन हमारा मानना है कि प्राकृतिक कारणों से जैसे मुद्रा रिसाव, बैंकों की आरक्षित निधि आवश्यकताएं, हमारे विभिन्न संचालन के माध्यम से जो हम करते हैं, चाहे वह स्पॉट हो, चाहे वह बिक्री -खरीद स्वैप परिचालन हो जो हम पहले करते थे, के कारण यह बहुत लंबी अवधि तक चलने वाली घटना नहीं हैं। हम इनका उपयोग करेंगे और यह चलनिधि समाप्त हो जाएगी।

संगीता मेहता:

आप कब तक संचरण होने की उम्मीद करते हैं?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि मैंने कहा, हम उम्मीद नहीं करते कि ये अधिशेष चलनिधि स्थितियां बहुत लंबे समय तक रहेंगी। इस वित्तीय वर्ष के भीतर ही, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चलनिधि का एक बड़ा हिस्सा, बिना संख्याएं दिए, ₹3-4 लाख करोड़ आमतौर पर किसी भी वर्ष में सीआईसी रिसाव होता है। फिर बिक्री -खरीद स्वैप जो हमने पहले किए हैं, हम कर रहे हैं। हमारे पास अन्य उपकरण जैसे ओएमओ, वीआरआर हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, स्पॉट हस्तक्षेप जो हम रुपये का समर्थन करने के लिए करते हैं। ये सभी चीजें, मैं उम्मीद नहीं करता, बिना आपको कोई संख्या दिए, कि चलनिधि बहुत लंबे समय तक इस तरह के उच्च अधिशेष मोड में रहेगी।

लता वेंकटेश:

सर, आप जानते हैं कि एफएक्स स्वैप रिज़र्व बैंक के लिए महंगे हैं। सीआरआर समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए सस्ता होगा। क्या यह बाहर है? मैं बस यह जोड़ना चाहती थी।

संजय मल्होत्रा:

कुछ भी नहीं है। आपने मुझसे अपने साक्षात्कार में भी पूछा था, मैं किसी भी विकल्प से इंकार नहीं करूँगा क्योंकि यह अभी भी एक विकसित और अनिश्चित दुनिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यह हमारे लिए चलनिधि समाप्त करने के लिए सबसे कम पसंदीदा तरीकों में से एक होगा। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जब आप लागत या खर्च या रिज़र्व बैंक के लिए लागत की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमें अर्थव्यवस्था के लिए लागत और अर्थव्यवस्था के लिए लाभों पर विचार करना चाहिए।

ये एफसीएनआर (बी) जमा भी रिज़र्व बैंक के लिए लागत पर कुछ प्रश्न उठाते हैं। मेरा मतलब है, यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी इसे समझते हैं, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी परिचालन हम कर रहे हैं, चाहे वह एफसीएनआर (बी) हो, चाहे वह कुछ चलनिधि परिचालन हो, चाहे वह मौद्रिक नीति में बदलाव हो, या समष्टि विवेकपूर्ण उपाय जो हम ले सकते हैं, उनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के लिए समग्र लाभों पर विचार करें। लाभ गौण है, या अधिशेष गौण है। मुख्य उद्देश्य पूरी अर्थव्यवस्था है, हमारे उपायों के परिणामस्वरूप हमें क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं थॉमसन रॉयटर्स से जसप्रीत कलरा को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। जसप्रीत, कृपया।

जसप्रीत कलरा, थॉमसन रॉयटर्स:

धन्यवाद, सर। गवर्नर, हमारा प्रश्न आईएनआर पर है। हमने देखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में अंतर्वाह आया है। आरबीआई भी हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन बाज़ार सर्वेक्षण और हेजिंग व्यवहार के माध्यम से, हमें लगता है कि बाजार इस बात से आश्वस्त नहीं है कि रुपये के अवमूल्यन का रुझान समाप्त हो गया है। क्या यह आपको चिंतित करता है? आप उस समस्या का क्या निदान करते हैं? और यह हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है, भले ही यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि भारत जब भी आवश्यकता होती है, तब प्रवाह ले सकता है और रुपये की रक्षा कर सकता है?

संजय मल्होत्रा:

बाजार अल्पकाल में काफी अतार्किक हो सकते हैं। वे हो सकते हैं। यह केवल दीर्घकाल में है कि वे सही मूल्य ढूंढने में सक्षम होते हैं। मेरा मतलब है, यह आपके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है, मुझे लगता है।

जसप्रीत कलरा:

क्या आप वर्तमान रुपये बाजारों को अतार्किक बताएंगे?

संजय मल्होत्रा:

कई अनुमानों, जिसमें आरईईआर शामिल है, के अनुसार, रुपया अधिमूल्यित नहीं है, यह अवमूल्यित हो सकता है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं एनडीटीवी प्रॉफिट से अलेक्जेंडर मैथ्यू को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। एलेक्स, कृपया।

अलेक्जेंडर मैथ्यू, एनडीटीवी प्रॉफिट:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। मैं इस अवसर की सराहना करता हूं। मैं इस डिबेट के बारे में जानना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इसके बारे में कुछ समझाने में मदद कर सकते हैं – रुख में बदलाव पर, क्योंकि दर बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मत था। रुख में बदलाव के लिए दो विरोधी थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चर्चा हुई और बहुमत ने इस नीति में रुख में बदलाव की घोषणा करने की आवश्यकता क्यों महसूस की?

संजय मल्होत्रा:

तो, सर्वप्रथम, हम इस पर वोट नहीं करते। यह वोट नहीं है। यह एक दृष्टिकोण है। इससे आपको हमारी सोच का अंदाजा मिलता है, और जहाँ तक आगे की नीतिगत दिशा का सवाल है, तो अलग-अलग लोगों की सोच

थोड़ी अलग हो सकती है, है ना? तो अब, मेरा मतलब है, इस पथ के संबंध में, रुख में इस बदलाव का क्या अर्थ है, मैंने पहले ही इस रुख में बदलाव को सख्त बनाने के बारे में स्पष्ट किया है।

मुझे दो या तीन बातें स्पष्ट करने दें। भले ही हमारे अप्रैल 2025 के वक्तव्य में जो मैंने कहा था, मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सख्त होने का अर्थ है ब्याज दरें या मौद्रिक नीति जिसमें उच्च ब्याज दरें और उपयुक्त चलनिधि है, जो आर्थिक गतिविधि को प्रतिबंधित करेगी या रोकेगी।

जबकि निभाव का अर्थ है एक ढीली मौद्रिक नीति जहां ब्याज दरें कम हैं, चलनिधि, आदि, इसके अनुसार उच्च है, ताकि यह आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करें। और तटस्थ का अर्थ है दोनों नहीं। हमारे संदर्भ में, हमने इसका अधिक उपयोग आगे की नीति मार्गदर्शन के लिए किया है, न कि इस बात के लिए कि नीति स्वयं निभावकारी है या यह प्रतिबंधात्मक है। हम इसका उपयोग अपनी दरों और भविष्य की नीतिगत कार्रवाई के लिए एक संकेत के तौर पर कर रहे हैं। हम कैलिब्रेटेड शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए सख्ती का अर्थ है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दर कटौती अब नहीं है, और यह केवल वृद्धि या ठहराव है जो संभव है।

कैलिब्रेटेड का अर्थ है, यह एक सौम्य रूप है। आप सभी समझते हैं कि यह सख्ती का एक सौम्य रूप है जहाँ निर्णय अधिक सोच-समझकर लिए जाने चाहिए, और बदलती व्यापक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप अधिक सटीक होने चाहिए। इसलिए, यह पहले से तय होने के बजाय डेटा पर ज़्यादा निर्भर है कि बढ़ोतरी होगी ही होगी।

अलेक्जेंडर मैथ्यू:

गवर्नर, स्पष्टीकरण के लिए, इसलिए आपने अपने भाषण में भी इसका उल्लेख किया था, लेकिन प्रभावी रूप से आप मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुद्रास्फीति की द्वैतता के बारे में बात कर रहे थे और आप इसके द्वितीयक प्रभाव का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए केवल स्पष्टीकरण के लिए।

संजय मल्होत्रा:

हां। तो, हम वास्तव में नहीं जानते कि प्रभाव क्या हो सकते हैं, और इसलिए हमें डेटा-निर्भर होना होगा, और संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। और हम इस उद्देश्य का पालन करते रहेंगे जो हमें दिया गया है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं ईटी नाउ से पीयूष शुक्ला को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। पीयूष, कृपया।

पीयूष शुक्ला, ईटी नाउ:

शुभ अपराह्न, गवर्नर, डीजी। धन्यवाद, ब्रिज सर। गवर्नर सर, थोड़ी देर पहले, आपने कहा था कि आपने बताया कि जब लागत की बात आती है, तो आपको उस लागत का भी ध्यान रखना पड़ता है जो आरबीआई उठाता है, और आपको अर्थव्यवस्था के व्यापक हित को भी ध्यान में रखना पड़ता है। 15 अक्टूबर से, एमडीआर लागू किया जा रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, चिंतित हैं, कि क्या संख्याएं घट सकती हैं और क्या आरबीआई को बिल चुकाना चाहिए? सबसे पहले, क्या आपको लगता है कि संख्याएं घटेंगी? और क्या आरबीआई अच्छे के लिए बिल चुकाने पर विचार कर सकता है? और सर, सिर्फ एक, आरबीआई द्वारा शीर्ष ऊपरी लेयर को अस्वीकार करने के बारे में एक व्यापक चर्चा चल रही है...

संजय मल्होत्रा:

आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं? कृपया सीमित रहें। उस अनुशासन को बनाए रखें, ठीक है?

पीयूष शुक्ला:

ठीक है, सर। मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इस पर पूछना चाहता था। अगर कोई और नहीं पूछता, तो मैं वापस आऊंगा।

संजय मल्होत्रा:

देखिए, एमडीआर, पहले से ही एक निर्णय लिया जा चुका है। फिलहाल, हमें वॉल्यूम में कोई कमी नहीं दिख रही है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि एक छोटी सी फीस का वॉल्यूम पर कोई बड़ा असर पड़ेगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मिंट से शयान घोष को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। शयान, कृपया।

शयान घोष, मिंट:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। मेरा प्रश्न यह है कि इस पूरे प्रकरण के संबंध में कि एक होल्डिंग कंपनी को सूचीबद्ध करने के लिए जोर दिया जाए, भले ही आवश्यकता हो तो कानूनी मार्ग अपनाया जाए, आपको लगता है कि यह किसे संदेश भेजता है...

संजय मल्होत्रा:

आप जानते हैं मेरा उत्तर।

शयान घोष:

मैं अनुमान नहीं लगाना चाहूंगा।

संजय मल्होत्रा:

नहीं, देखिए, हम किसी एक विशिष्ट या संबंधित संस्था से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है? इसलिए कृपया हमारे साथ धैर्य रखें। यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम आपके पास वापस आएंगे। लेकिन आप इन प्रश्नों को पूछकर अपना अवसर बर्बाद कर रहे हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं इनफॉरमिस्ट मीडिया से आर्यन खन्ना को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। आर्यन, कृपया।

आर्यन खन्ना, इनफॉरमिस्ट मीडिया:

धन्यवाद, सर। शुभ अपराह्न। तो, मेरा प्रश्न गवर्नर और डीजी गुप्ता दोनों से है, यदि संभव हो। भू-राजनीतिक माहौल के बावजूद पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 8% रही को देखते हुए, क्या आरबीआई के अनुमानों के अनुसार भारत की संभावित संवृद्धि दर के आकलन में वृद्धि हुई है? क्या इसका यह भी अर्थ है कि भारत की तटस्थ वास्तविक ब्याज दर अब अधिक है? क्योंकि यह एक सैद्धांतिक बाधा है, जैसे कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेश में, क्या भारत को पूंजी अंतर्वाह आकर्षित करने के लिए सामान्य रूप से अधिक तटस्थ वास्तविक दर की आवश्यकता है? यही प्रश्न है।

संजय मल्होत्रा:

संभावित संवृद्धि दर या संवृद्धि, हमारे पास कोई संख्या नहीं है। वास्तविक दर पर, हमने कुछ अनुमान दिए थे, लेकिन ये बहुत गतिशील हैं, मापने में कठिन, गतिशील और विकसित हो रहे हैं। आज की वास्तविक दर क्या होगी, मेरा मतलब है - जो भी उनके लायक हैं, कुछ अध्ययन किए गए हैं। हम आपको उन संख्याओं को देंगे। लेकिन वैश्विक व्यापक स्थिति को देखते हुए, जैसा कि आपने बताया है, इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं - जो अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग होंगे।

इसलिए, यदि किसी देश में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति है, जो लंबे समय से बनी हुई है - तो यह स्थिति भारत से बिल्कुल अलग है, जहाँ मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी सिर्फ हाल के महीनों में ही देखने को मिली है। यदि इन देशों में जीडीपी के मुकाबले सार्वजनिक उधार का स्तर बहुत अलग-अलग है, तो ब्याज दरें भी अलग-अलग होंगी। इसलिए, इनका वैश्विक स्थिति पर असर पड़ता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता; लेकिन हर देश में वहां की ब्याज दरों के अनुसार अलग-अलग कारण या अलग-अलग परिस्थितियां हो सकती हैं।

आर्यन खन्ना:

समझ गया।

संजय मल्होत्रा:

क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? [DG(PG)]

डॉ. पूनम गुप्ता:

जरूर। तो आपके सवाल के तीन हिस्से थे। संभावित जीडीपी वृद्धि पर, यदि आप पिछले कुछ वर्षों को देखें, विशेष रूप से कोविड के बाद, तो आप देखेंगे कि वृद्धि दर एकाधिक वैश्विक झटकों के प्रति अत्यधिक लचीली रही है, और यह वृद्धि दर निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति के साथ अस्तित्व में रही है। यह संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर अधिक है। यहां तक कि पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर बहुत कम मुद्रास्फीति के साथ अस्तित्व में रही, और यह इस वर्ष भी ऐसा ही होता यदि दो अर्थात जलवायु और तेल की कीमतों के वैश्विक झटके नहीं होते। और बहुत सारे संकेतक हैं। हमारे पास कोई विशिष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन संकेतक दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्ति और क्षमता बढ़ गई है।

प्राकृतिक वास्तविक ब्याज दर पर, हमने एक व्यापक साहित्य सर्वेक्षण किया है। हमने अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ नोट्स का आदान-प्रदान किया है। जैसा कि सर ने उल्लेख किया, यह एक अत्यधिक सैद्धांतिक, तरल अवधारणा है, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आवश्यक रूप से मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। आपका तीसरा सवाल था, वैश्विक स्तर पर पूंजी की लागत बढ़ रही है, इसके भारत के लिए क्या प्रभाव होंगे? यदि आप वास्तव में देखें - पहले आप बिल्कुल सही हैं, हाइपरस्केलर्स और अन्य नए स्रोतों और जो मांग उभर रही है, से पूंजी की मांग बढ़ रही है।

लेकिन यदि आप भारत को देखें, तो वहां दो या तीन कारक हैं जो हमें उन बढ़ती लागतों से अलग करते हैं। एक है हमारी वित्तीय सतर्कता, जो हमें न केवल हमारे परिसंपत्ति वर्ग में बल्कि अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से भी अलग करती है। हम नहीं देख रहे हैं कि सरकार से अत्यधिक मांग आ रही है, जैसा कि अन्य देशों में है। और दूसरा है कि हमारे पास बचत और निवेश के घरेलू स्रोत हैं, जो हमारी वैश्विक पूंजी पर निर्भरता को कम करते हैं।

इसलिए ये सभी कारक हमें अन्य कई देशों की तुलना में थोड़ा अधिक अलग करते हैं कि हमारे पास बचत के घरेलू स्रोत हैं, कॉर्पोरेट अभी भी बहुत अधिक नकदी रखते हैं, बैंक ऋण वृद्धि हम देख ही रहे हैं, जो हमें वैश्विक स्तर पर जो देख रहे हैं उससे अलग करता है। धन्यवाद।

आर्यन खन्ना:

समझ गया। बहुत- बहुत धन्यवाद। तो स्पष्टीकरण के लिए, सर। प्रमुख निष्कर्ष यह लगता है कि यदि भारत की मुद्रास्फीति-वृद्धि स्थिति से आपको दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ पकड़ बनाए रखने या बराबरी करने की आवश्यकता नहीं देखते हैं। क्या यह सही है?

संजय मल्होत्रा:

हां, सही है।

आर्यन खन्ना:

धन्यवाद, सर।

संजय मल्होत्रा:

मेरा मतलब है कि वृद्धि और मुद्रास्फीति गतिशीलता, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके साथ ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर क्या होनी चाहिए, जो वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, लेकिन अन्य कुछ देशों की तरह उतनी नहीं।

आर्यन खन्ना:

धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। धन्यवाद, मैडम।

सर, हम अब बाईं ओर से शेष प्रश्न लेंगे, और मैं मीडिया व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया केवल एक प्रश्न पूछें।

मैं अब फलकनाज सैयद, दक्कन क्रॉनिकल से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। फलकनाज, कृपया।

फलकनाज सैयद, दक्कन क्रॉनिकल:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। गवर्नर, क्या आपने बीमा विनियामक द्वारा प्रस्तावित वितरण सुधारों पर एक राय ली है, जिसने बैंकों द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पादों को बेचने से अर्जित कमीशन में बहुत तेज कटौती का प्रस्ताव रखा है? क्या आपने इस पर एक राय बनाई है, और आपका वहां क्या विचार है?

संजय मल्होत्रा:

हमने नहीं बनाई है। यदि आप मुझसे पूछें, आपने एक राय बनाई है, हमने कोई राय नहीं बनाई है। मुझे लगता है कि विनियामक स्पष्ट रूप से - सबसे पहले, यह एक मसौदा है, इसलिए वे सभी हितधारकों, जिसमें उद्योग और उपभोक्ता समूह आदि शामिल हैं, से टिप्पणियां लेंगे। यह मुख्य रूप से, मुझे लगता है, उपभोक्ता हित में है, लागत को कम करने के लिए, और साथ ही गलत बिक्री को रोकने या कम करने के लिए। वे उपभोक्ताओं और उद्योग के सर्वोत्तम हित में एक निर्णय लेंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं ललातेंदु मिश्रा, द हिंदू से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। ललातेंदु, कृपया।

ललातेंदु मिश्रा, द हिंदू:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। मेरा प्रश्न अनूप द्वारा पूछे गए प्रश्न का एक अतिरिक्त प्रश्न है। अमेरिका से 100% तक टैरिफ का खतरा है, और वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि यह एक शिखर पर पहुंच गया है क्योंकि अमेरिका अधिक मांग रहा है, जो आप अधिक नहीं दे सकते। यदि समझौता नहीं होता है, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है, सर? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

देखिए, हम पहले से नहीं जानते हैं, कौन से क्षेत्र, आदि, किस हद तक ये टैरिफ लागू किए जाएंगे। इसलिए, वास्तव में उत्तर देना अप्रासंगिक है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा। साथ ही, हमारे पास हाल ही में कई व्यापार समझौते हैं, जिनमें से कुछ संचालन में हैं, अन्य पाइपलाइन में हैं। वे मदद करेंगे। साथ ही उद्योग ने अपने निर्यात को विविधता दी है। ये सभी चीजें, मुझे लगता है, इसके प्रभाव को कम करेंगी यदि कुछ क्षेत्रों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं नचिकेत केलकर, बिजनेस टुडे से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। नचिकेत, कृपया।

नचिकेत केलकर, बिजनेस टुडे:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। मेरा प्रश्न 1 अक्टूबर से प्रभावी हुए नए फेमा नियमों से संबंधित है। नए निर्यात घोषणा फॉर्म के संबंध में बहुत सी शिकायतें या चिंताएं उठाई जा रही हैं जिसे अब भरना है। यहां तक कि छोटे फ्रीलांसर्स या सामग्री निर्माता भी उस फॉर्म के अधीन हैं, जो कहते हैं कि यह आसानी से कारोबार करने के बारे में हम जो बात करते हैं उसके विपरीत है। क्या आरबीआई इनमें से कुछ चीजों पर फिर से विचार करेगा? आपकी इस पर क्या राय है?

संजय मल्होत्रा:

रोहित [डीजी(आरजे)], क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे?

रोहित जैन:

नए व्यापार विनियमन जनवरी में जारी किए गए थे, अक्टूबर 1 की समय- सीमा से पर्याप्त रूप से पहले। वे 1 अक्टूबर से प्रभावी हुए हैं। और इन नए व्यापार विनियमन को लाने का पूरा उद्देश्य प्राधिकृत डीलरों द्वारा

व्यापार मामलों को संभालने के लिए उदार बनाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, आसानी से कारोबार करने को बढ़ावा देना है।

और सेवा निर्यात और आयात को अब रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया है, लेकिन व्यक्तियों को व्यक्तिगत प्रकृति के संविदाओं के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बाहर रखा गया है। इसलिए, रिपोर्टिंग दायित्वों के संबंध में कुछ गलतफहमी लगती है, जिसे हम शीघ्र ही एक FAQ के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। लेकिन नए व्यापार विनियमन का पूरा दायरा मामलों को सरल बनाने, प्राधिकृत डीलरों पर बोझ को कम करने, और संबंधित निर्यातकों और आयातकों पर भी बोझ को कम करने के लिए एक कदम आगे है। यह एक सकारात्मक अर्थ में एक आगे की ओर कदम है।

संजय मल्होत्रा:

मैं दो और स्पष्टीकरण दूंगा। एक स्पष्टीकरण जो उन्होंने दिया है, वह यह है कि, व्यक्तियों के रूप में, चाहे आयात के लिए या निर्यात के लिए, राशि जो भी हो, रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस संबंध में कुछ संदेह है। उन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यदि आप किसी टीवी चैनल या ऐप या कुछ पत्रिकाओं या अखबारों की सदस्यता ले रहे हैं, या दूसरी ओर, व्यक्ति के रूप में बाहर कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूटरिंग सेवाएं, कुछ छोटे सॉफ्टवेयर आदि, और उनके लिए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, तो वे, व्यक्तियों के रूप में, रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक नहीं हैं। जैसा कि रोहित [डीजी(आरजे)] द्वारा पहले स्पष्ट किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसे आपके दर्शकों के लाभ के लिए दोहरा रहा हूं।

और दूसरा छोटी राशियों के लिए, यहां तक कि निर्यातकों के लिए, यदि राशि छोटी है, प्रति बिल ₹10 लाख तक, वार्षिक नहीं, प्रति बिल ₹10 लाख, तो एक स्व-घोषणा पर्याप्त होगी। एक चालान में, अपलोड करने और चालान देने के बारे में कुछ चिंता है, लेकिन ₹10 लाख तक, एक विकल्प दिया गया है, जो एक स्व-घोषणा फॉर्म के रूप में है।

तीसरा, पोर्टल पर जो हमारे पास है, रिपोर्टिंग बैंकों और एडी द्वारा, मध्यस्थों द्वारा की जानी है, और एकल निर्यातकों और आयातकों द्वारा नहीं। उन्हें केवल यह जानकारी एडी या बैंकों को प्रदान करना है।

अब, इस जानकारी में से कुछ वे पहले से ही प्रदान कर रहे थे। भुगतान के समय, वे एक उद्देश्य कोड और कुछ अन्य जानकारी प्रदान कर रहे थे। कुछ अधिक जानकारी है जो हमने उनसे प्रदान करने के लिए कहा है, और यह केवल सेवा निर्यात के संबंध में हमारी डेटा रिपोर्टिंग और डेटा उपलब्धता को बेहतर बनाएगा। और इसलिए, हम महसूस करते हैं कि यह कोई बड़ी असुविधा या बोझ नहीं है। माल व्यापार के लिए वस्तु, यह पहले से ही हो रहा है। इस अर्थ में, हमने सेवाओं को माल व्यापार के समान लाने की कोशिश की है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं अब बेन जोस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। बेन, कृपया।

बेन जोस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस:

हाय, गवर्नर। आपने संवृद्धि अनुमान में 40 आधार अंक बढ़ोतरी की। आपने दर में 25 आधार अंक बढ़ोतरी की। क्या यहां कोई असंगति है? जब आप ब्याज दर बढ़ाते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए होता है, है ना? इसका वृद्धि पर प्रभाव होना चाहिए। लेकिन आप दर बढ़ा रहे हैं क्योंकि - और आप कहते हैं कि, ठीक है, उच्च दरें लंबे समय तक होंगी। आप अपना रुख बदलते हैं। फिर भी, आप संवृद्धि अनुमान बढ़ाते हैं। क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि संचरण विलंबित होगा? क्योंकि प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि है, इसलिए बैंक नए ग्राहकों को दर नहीं पास करेंगे? यह दो अलग-अलग कैसे है।

संजय मल्होत्रा:

मैंने आपके प्रश्न को नहीं समझा।

बेन जोस:

सर, वृद्धि अनुमान बढ़ाकर...

संजय मल्होत्रा:

40।

बेन जोस:

40 आधार अंक?

संजय मल्होत्रा:

हां

बेन जोस:

तो, यदि ब्याज दरें - क्योंकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग है, इसलिए आप मांग को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए आप दर बढ़ाते हैं। दर वृद्धि का वृद्धि पर क्या प्रभाव है?

संजय मल्होत्रा:

नहीं, मैंने इसे स्पष्ट किया। मुझे लगता है, अगर आप संकल्प पढ़ें, तो हमने उल्लेख किया है कि कुछ 3-4 चैनल हैं, लेकिन व्यापक रूप से तीन चैनल हैं। एक तो बस पुनर्प्रतिरूपण है, क्योंकि दरें एक ऐसे परिवेश में थीं जब यह बहुत, बहुत कम थीं। इसलिए यह पुनर्प्रतिरूपण चैनल है, जहां मुद्रास्फीति एक तरह से सामान्यीकरण हो रही है।

दूसरा है आपूर्ति-पक्ष चैनल, क्योंकि ऊर्जा की उच्च कीमतें और कुछ भोजन आदि हैं, इसलिए कुछ आपूर्ति-पक्ष दबाव हैं। और आपूर्ति-पक्ष दबाव के भीतर, हमने कहा कि तीन चैनल हैं। एक प्रत्यक्ष चैनल है, एक अप्रत्यक्ष चैनल है, और एक द्वितीयक प्रभाव चैनल है।

और फिर हमने मांग कहा, जो तीसरा चैनल है। और हमने विस्तार से कारण बताए हैं कि हम देख रहे हैं कि कहां से दबाव आ रहा है और किस हद तक हम उन दबावों को प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत, बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।

इसलिए, वर्तमान में, हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण निश्चित रूप से हो रहा है, और इसलिए पुनर्प्रतिरूपण आवश्यक है, जैसा कि एमपीसी ने उल्लेख किया है। और हमें कुछ संकेत, हालांकि सीमित, द्वितीयक प्रभावों के संकेत मिल रहे हैं, जिन्हें अप्रत्यक्ष प्रभावों से अलग करना मुश्किल है। और हम अधिक निकटता से डेटा को देखेंगे कि क्या हमें अधिक करने की आवश्यकता है या नहीं।

और इसी तरह, मांग के लिए, हमें सीमित, बहुत सीमित संकेत मिल रहे हैं। भले ही वृद्धि लचीली है, हमें इसका कीमतों पर दबाव नहीं दिख रहा है, आपने देखा होगा कि कंपनियों की मार्जिन बढ़ रही है, जो हम नहीं देख रहे हैं, उदाहरण के लिए, है ना? उदाहरण के लिए, मांग-पक्ष दबाव बहुत सीमित हैं, भले ही समग्र, मौद्रिक और ऋण समग्र यह बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप फिर से देखें।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मनीष सुवर्णा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। मनीष, कृपया।

मनीष सुवर्णा, पीटीआई:

शुभ अपराह्न, सर। सर, नीति वक्तव्य में, आपने उल्लेख किया है कि संभावित लचीली गैर-कृषि गतिविधि ग्रामीण उपभोग का समर्थन जारी रखेगी। लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि आप कितने आश्वस्त हैं कि यह संभावित लचीली गैर-कृषि गतिविधि, ग्रामीण आय और ग्रामीण उपभोग में किसी भी आगे की कमजोरी को पूरी तरह से मदद कर सकती है, जब कि हम देख रहे हैं कि मानसून कमजोर है?

संजय मल्होत्रा:

हमने इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखा है और उस आधार पर, कृषि उत्पादन में कुछ मंदी है। इसलिए, और इसी तरह ग्रामीण मांग, और इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष लगभग 8% वृद्धि के उच्चतम स्तर से, हम इस वर्ष 7.1% पर हैं, और यहां तक कि पहली तिमाही भी 7.1% है। ये सभी चीजें हमारे अनुमानों में शामिल की गई हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं सौरभ पांडेय, आईएएनएस से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। सौरभ, कृपया।

सौरभ पांडेय, आईएएनएस:

शुभ अपराह्न, गवर्नर, सर। सर, आपने हाल ही में कहा था कि वैश्विक एआई शेयरों में फैली मूल्यांकन, वित्तीय स्थिरता के लिए एक प्रमुख जोखिम पेश करती है और इसमें सुधार, विदेशी पूंजी को भारत जैसे उभरते बाजारों में फिर से निर्देशित कर सकता है। यदि आप कृपया इस पर विस्तार से बता सकते हैं।

संजय मल्होत्रा:

क्या आप कौटिल्य में मेरे भाषण का उल्लेख कर रहे हैं? हां, तो, देखिए, वह भाषण अधिक वैश्विक दर्शकों के संदर्भ में था, यह अधिक वैश्विक जोखिमों के संदर्भ में था जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए हैं, और उस संदर्भ में, भारत के लिए जोखिम क्या हैं। इसलिए एआई निश्चित रूप से फैली मूल्यांकन, उनका सुधार, अचानक सुधार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चिंता हो सकता है। लेकिन भारत के लिए, चूंकि हमारे पास यहां बहुत अधिक एआई नहीं है, हम इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखते हैं। यदि कुछ हो सकता है, तो यह सकारात्मक हो सकता है, यदि कुछ हो सकता है। यही वह संदर्भ था जिसका उल्लेख मैंने उस भाषण में किया था।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं आकाश मंडल, इंडियन एक्सप्रेस से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। आकाश, कृपया।

आकाश मंडल, इंडियन एक्सप्रेस:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। आपने अपने वक्तव्य में कहा था, और आपने अभी भी उल्लेख किया है, कि इस बात के सीमित संकेत हैं कि आपूर्ति-पक्ष के दबाव कीमतों के निर्धारण के व्यवहार में स्थायी रूप से शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि खुदरा मुद्रास्फीति में लगभग उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी हमने पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद थोक और उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति में देखी है।

क्या आप देखते हैं कि पास-थ्रू होगा और ये दोनों सामान्य हो जाएंगे, आगे चलकर? क्या आप इसे निकट भविष्य में देखते हैं? और अगले दो-तीन महीनों के लिए आपके 5.8% के मुद्रास्फीति अनुमान में, आपने इसे किस सीमा तक शामिल किया है? विशेषकर तब, जब मांग की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है और आपने संवृद्धि दर के अनुमानों को भी बढ़ा दिया है? मैं बस इस बारे में थोड़ी और जानकारी चाहता था।

संजय मल्होत्रा:

तो, हमने देखा है जैसा कि उल्लेख किया गया है। हमने केवल आंशिक पास-थ्रू देखा है। इसमें से कुछ हो रहा है और होगा। अब यह किस हद तक होगा, यह आपूर्ति-पक्ष दबावों की निरंतरता पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें आगे चलकर अपनी नीति के संबंध में डेटा-निर्भर रहने की आवश्यकता है। हम पहले से ही देख रहे हैं कि 37% वस्तुएं 4% मुद्रास्फीति दर से अधिक हैं। और यह जारी रह रहा है। अब, यह किस हद तक आगे पास होगा, यह हमें देखना होगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। हम शेष प्रश्न दाईं ओर से लेंगे। मैं रामकुमार, द हिंदू बिजनेस लाइन से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। रामकुमार, कृपया।

के रामकुमार, द हिंदू बिजनेस लाइन:

सर, बैंक और एनबीएफ़सी जब ऋण वृद्धि के मामले में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो क्या यह ब्याज दर में वृद्धि, ऋण की मांग को वास्तव में धीमा नहीं कर देगी?

संजय मल्होत्रा:

स्वामीनाथन [(DG(SJ)], क्यों न आप इस पर जवाब दें?

स्वामीनाथन जे:

जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ऋण वृद्धि लगभग 18-19% तक पहुँच गई है; इसे हम 'ऑल-टाइम हाई' तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम पिछले एक दशक का सबसे ऊँचा स्तर ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन यदि हम 10 वर्षों का लंबे समय का औसत लें, तो आमतौर पर यह 12% से 14% की सीमा में देखा जाता है, जो बहुत स्थायी और वृद्धि का समर्थन करने वाला है।

हाँ, जैसा कि हमने देखा है, इन दरों के प्रभाव को पूरी तरह से सामने आने में आमतौर पर लगभग दो तिमाहियों का समय लग जाता है। मांग और दर दोनों के संबंध में कुछ मंदी होगी। लेकिन 20% से 18% तक मंदी बुरी नहीं है और वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होगी।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मयूर शेट्टी, द टाइम्स ऑफ इंडिया से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। मयूर, कृपया।

मयूर शेट्टी, टाइम्स ऑफ इंडिया:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। गवर्नर, बीमा विनियामक ने अपने वितरण सुधारों में बैंकों को लक्षित किया है। मेरा मतलब है, यह बैंकों को कई तरीकों से प्रभावित करता है, उनकी शुल्क आय, उत्पाद, क्रेडिट लाइफ, और उन्होंने उनके व्यवहार पर भी टिप्पणी की है। यह मुद्दा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी बैंक बिक्री के लिए था। क्या इस पर विनियामकों के बीच कोई समन्वित कार्रवाई होगी?

संजय मल्होत्रा:

यह बीमा विनियामक के क्षेत्र में है तय करने के लिए कि वे बीमा उत्पादों के वितरण को कैसे और क्या करना चाहते हैं। हम उन्हें अपनी टिप्पणियां देंगे जैसा कि उल्लेख किया गया है, हमने इस पर अपनी राय तय नहीं की है। हम उन्हें अपनी टिप्पणियां देंगे।

मयूर शेट्टी:

धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं अब श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। श्यामा, कृपया।

श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:

नमस्कार, सर। सर, 2026 का मानसून 2000-2001 के बाद से सबसे शुष्क रहा है, और कई राज्य जैसे बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, उन्होंने औसत से कम वर्षा प्राप्त की है। आगे चलकर, यह घरेलू क्षेत्र के लिए क्या अर्थ रखता है? आप वर्तमान में बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच स्थिति का कैसे आकलन करते हैं?

संजय मल्होत्रा:

ज़ाहिर है, इसका प्रभाव है। लेकिन जैसा कि उल्लेख किया गया है, वर्षों के साथ प्रभाव कम हो रहा है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, फार्म और गैर-फार्म, मिलाकर, लचीलापन बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप कई उपाय लिए गए हैं, जैसे कि सिंचाई के उपयोग में वृद्धि, अधिक जलवायु-प्रतिरोधी किस्मों और कृषि प्रथाओं का अभ्यास फार्म में, और इसी तरह गैर-फार्म में भी। इसलिए, जबकि उनकी आय पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, हम महसूस करते हैं कि वे काफी लचीले होंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं क्षिप्रा पेटकर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। शिप्रा, कृपया।

क्षिप्रा पेटकर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:

धन्यवाद, सर। शुभ अपराह्न, गवर्नर। ईसीएल कार्यान्वयन के साथ अब केवल 6 महीने बचे हैं, बैंकों की तैयारी के संबंध में आरबीआई का आकलन क्या है? और आपकी उनसे चर्चाओं में, क्या उन्होंने कोई प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियां उठाई हैं? यदि आप विस्तार से बता सकते हैं तो।

संजय मल्होत्रा:

शिरीष [डीजी(एससीएम)], क्या आप इस पर बात करना चाहेंगे?

शिरीष सी. मुर्मू:

देखिए, यह ईसीएल ढांचा, हमने बहुत पहले जारी किया था। इसलिए, स्पष्ट रूप से, बैंक अच्छी तरह से तैयार हैं और अन्यथा भी हम बैंकरों से संपर्क में हैं, और जब भी हम बातचीत करते हैं, यदि कोई मुद्दे हैं तो हम उस पर विचार करते हैं।

हमारा आकलन है कि संचरण सरल होगा। हमें नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। और निश्चित रूप से, जब हमने इस ढांचे को जारी किया था, तो हमने उस समय एक बैक टेस्टिंग भी की थी, और हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा, हम एक वर्कशॉप भी आयोजित कर रहे हैं जहां हम स्पष्टीकरण देते हैं और हैंडहोल्डिंग करते हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं अब सौरव मुखर्जी, एएनआई से अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। सौरव, कृपया।

सौरभ मुखर्जी, एएनआई:

धन्यवाद, गवर्नर सर। आपके उद्घाटन वक्तव्य में, आरबीआई ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एआई को एक जोखिम के रूप में चिह्नित किया है। आपको क्या विशेष रूप से चिंतित कर रहा है, सर? एआई-संचालित संपत्ति बुलबुले का जोखिम, श्रम बाजार में व्यवधान, या वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव?

संजय मल्होत्रा:

ये सभी जोखिम महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि केंद्रीय बैंकरों के तौर पर हमारे लिए, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण साइबर जोखिम हैं। इस युग में, जब सभी प्रणालियों द्वारा आईटी का उपयोग किया जा रहा है और जब वित्तीय प्रणालियों के बीच कोई सीमाएँ नहीं हैं और वे एक-दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, एआई इसमें एक और आयाम जोड़ता है, और इसलिए हमें इन संबंध में बहुत सावधान रहना होगा। हम पहले से ही अपने विनियमन और पर्यवेक्षण विभागों के माध्यम से कई उपाय ले रहे हैं, और हम अपनी प्रणालियों को मजबूत बना रहे हैं ताकि हम साइबर जोखिमों को उत्पन्न होने से रोक सकें और उन्हें कम कर सकें।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं आकाशवाणी से प्रार्थना से अपना प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा। प्रार्थना, कृपया।

सी. प्रार्थना, आकाशवाणी:

शुभ अपराह्न, गवर्नर। आज जारी आरबीआई के वक्तव्य में वित्तीय बाजारों के लिए एक तकनीकी परामर्शदाता समिति के गठन का उल्लेख है। क्या आप कृपया इस पर विस्तार से बता सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

रोहित [डीजी (आरजे)], क्या आप इसे लेना चाहेंगे? यह आपका विषय है।

रोहित जैन:

जैसा कि हमने देखा है, वित्तीय बाजार विस्तारित और गहन हो रहे हैं, बहुत सारे सुधार किए गए हैं, और हम बाजारों को आगे मजबूत बनाने और आगे विकसित करने के लिए विभिन्न विनियामक उपाय कर रहे हैं।

हम पहले से ही बाजार प्रतिभागियों के साथ बहुत सारे जुड़ाव कर रहे थे, बहुत सारी बातचीत होती थी, लेकिन हमने सोचा कि, वैश्विक स्तर पर देखी जा रही चरम अस्थिरता और संरचित तरीके से विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए, हम इस व्यवस्था को संस्थागत बना रहे हैं जहां हम विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति का गठन करेंगे।

और हम नियमित अंतराल पर उनसे मिलेंगे ताकि उनके इनपुट, उनके सुझाव प्राप्त कर सकें, जिसका पूरा उद्देश्य यह है कि हम नीति निर्माण में सुधार कर सकें और वित्तीय बाजारों के सामने आने वाले संचालन संबंधी मुद्दों को भी बेहतर ढंग से समझ सकें और इससे संबंधित बेहतर समझ और जानकारी प्राप्त कर सकें, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे वित्तीय बाजारों के विकास के समग्र कारण में मदद करेगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब हम अंतिम मीडिया व्यक्ति के पास आते हैं। मैं निक्के के सौम्यजीत साहा से अपना प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा। सौम्यजीत, कृपया।

सौम्यजीत साहा, निक्के:

धन्यवाद, गवर्नर। मेरे पास कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि घरेलू तेल कीमत का अनुमान क्या है, यदि अगस्त से बदल गया है, और यदि बदल गया है, तो आपके उन अनुमानों में बदलाव के पीछे क्या तर्क है।

संजय मल्होत्रा:

क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? [डीजी (पीजी)]

डॉ. पूनम गुप्ता:

जरूर। तेल कीमत के अनुमान एमपीआर में दिए गए हैं, जो इस बार नीति के साथ जारी किए गए हैं। यह 5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल बढ़ गया है, और कारण यह है कि संघर्ष का बढ़ना, कीमतों का उच्च स्तर पर बने रहना, और अग्रिम बाजारों का अनुमान है कि कीमतें पिछली कुछ नीतियों में देखी गई थीं, उससे अधिक होंगी। इसलिए, एक साथ लिया जाए तो यह एक वृद्धि है, लेकिन मात्रात्मक रूप से यह बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, स्थिति विकसित हो रही है, और वर्तमान समय में वार्षिक औसत कैसा निकलेगा, इसका हमारा सर्वोत्तम अनुमान है।

संजय मल्होत्रा:

95 अमेरिकी डॉलर?

डॉ. पूनम गुप्ता:

95 अमेरिकी डॉलर, हां।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर, और धन्यवाद, मैडम। सर, आपकी अनुमति से, हम अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी टीवी18:

सिर्फ एक और, सर। रुपया आज 50 पैसे गिर गया है, सर। यह ₹ 96.96 के सर्वकालिक निम्न स्तर के बहुत करीब है। हम ₹96.83 पर हैं। क्या कोई प्रतिक्रिया है, कोई आगे के कदम? क्या हमें चिंतित होना चाहिए?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सुनिश्चित करेंगे कि रुपया स्थिर हो, रुपया अपना सही मूल्य पाए, और हम रुपये के एक सुव्यवस्थित गति और अपना सही मूल्य ढूंढने में रुपये का समर्थन करेंगे, और साथ ही, अत्यधिक अस्थिरता न हो यह सुनिश्चित करेंगे।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:

सर, अंग्रेजी में 24 प्रश्न थे और केवल 02 हिंदी में। और सर, एक बहुत बड़ी घोषणा थी...

संजय मल्होत्रा:

आप केवल दो लोग हैं, इसलिए दो हैं।

अनुराग शाह:

सर, लेकिन देश की जनसंख्या 100 करोड़ है। सर, यह एक बहुत बड़ी घोषणा थी। आम लोगों से संबंधित एक बड़ी घोषणा की गई थी, और किसी ने इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा, सर। यह अकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित था...

संजय मल्होत्रा:

बहुत-बहुत धन्यवाद, अन्यथा। मैं स्वयं इसका उल्लेख करने वाला था।

अनुराग शाह:

सर, तो प्रश्न इससे संबंधित है, और...

संजय मल्होत्रा:

चूंकि आपने पूछा, यह अच्छा है। कृपया पूछें।

अनुराग शाह:

सर, कुछ संदर्भ प्रदान करना है ताकि लोग लाभ समझ सकें। सर, मई-जून में, आपके द्वारा बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बेचे जाने वाले वित्तीय उत्पादों के संबंध में एक मसौदा जारी किया गया था, जिसमें बीमा भी शामिल है, और उसे आगे ले जाते हुए, आईआरडीएआई ने भी एक चर्चा पत्र जारी किया था जहां अंत में, यह लोगों को लाभ पहुंचाएगा, बैंकिंग ग्राहकों को लाभ पहुंचाएगा। और सर, यह अकाउंट एग्रीगेटर, यह कितनी बड़ी गतिविधि है, और आम जनता के लिए, ग्रामीण के लिए ...

संजय मल्होत्रा:

मैं इसे समझाना चाहता था। सभी के सुविधा के लिए, आपने पहले अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में नहीं पूछा, लेकिन आपने अंत में पूछा, इसलिए धन्यवाद कि आपने इस पर ध्यान दिया। हां?

अनुराग शाह:

हां, सर, अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में...

संजय मल्होत्रा:

अकाउंट एग्रीगेटर एक महत्वपूर्ण साधन है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी कृपया इसकी जानकारी प्रसारित करें, क्योंकि यह न केवल अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में आपके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह आपको अपनी सभी वित्तीय संपत्तियों का एक अवलोकन देता है।

और इसलिए, यह अब उस जानकारी को एकीकृत करने का एक कदम है, जो पहले कई अकाउंट एग्रीगेटरों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी। मुझे लगता है कि कम से कम 15 अकाउंट एग्रीगेटर हैं, इसलिए जानकारी काफी विखंडित थी। और उन्हें एकीकृत करके, अब आपके लिए एक व्यक्ति के रूप में, और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए संभव है - यह बीमा ब्रोकर हो सकते हैं, संपत्ति प्रबंधक हो सकते हैं, और निवेश सलाहकार आदि, सहमति के साथ, व्यक्ति की सहमति के साथ, डेटा लेकर और हम सभी को उचित सलाह दे सकते हैं।

यह एक बात है, और दूसरा यह है, आप में से कुछ लोगों को एक सीएएस, एक समेकित खाता विवरण मिलेगा। इसमें बैंक जमाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जो कि एक कमी है। इसलिए, हम अब यह सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी बैंकों के बैंक जमा से संबंधित जानकारी, जो पहले से ही ऑनबोर्ड हैं, और शेष समय के साथ, किसी भी अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से आपको सीएएस के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। बहुत- बहुत धन्यवाद।

हंसिनी कार्तिक:

आप यह क्यों कर रहे हैं, सर? बैंक जमा को सीएएस में शामिल करने का तर्क क्या है?

संजय मल्होत्रा:

क्या आप उस जानकारी को नहीं चाहेंगे? मेरा मतलब है, मैं चाहूंगा कि मेरे पास यह जानकारी हो, यानी मेरा समेकित खाता विवरण। और इसलिए, एक नज़र में, हर महीने, यदि मुझे वह जानकारी मिलती है, तो मुझे लगता है कि यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है। हम बहुत से बैंकों, बहुत से मामलों में देखते हैं, जिसमें बैंक जमा खो जाते हैं, और विशेष रूप से जब लोग मर जाते हैं, आदि। और इसलिए, यह उसमें भी मदद करेगा, क्योंकि आपके पास अपनी सभी वित्तीय संपत्तियों का एक विवरण देख पाएंगे।

एक्ता सूरी:

सर, विनियामक ने भी एक निदेश जारी किया - उन्होंने सुझाव दिया कि पैसे अवैध (म्यूल) खातों में जाने से कैसे रोका जाए ताकि लोग अपना पैसा वापस पा सकें - आपने एक मसौदा जारी किया जिसमें बताया गया कि पैसे को ब्लॉक किया जाना चाहिए, और यदि खाता बहुत संदिग्ध है, तो यह एक म्यूल खाता बन जाता है। तो, सर, जन हित में, हम जानना चाहेंगे, किसी व्यक्ति को इसे कितनी जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए, और यदि पैसा एक खाते में चला गया है और इसे पहले ही निकाल लिया गया है, तो इसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में पीड़ित को क्या करना चाहिए?

संजय मल्होत्रा:

इसके लिए पहले से ही एक एसओपी जारी की गई है, और उस एसओपी के तहत, जितनी जल्दी आप सूचित करेंगे, उतनी जल्दी जानकारी बैंकों तक पहुंचेगी, जिससे खाता या राशि, जो भी हो, फ्रीज़ किया जा सके और मालिक को वापस कर दी जा सके। इसलिए, इसे जितनी जल्दी संभव हो सके, करना चाहिए। धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद सर। सभी की सहभागिता के लिए धन्यवाद, और आगे का दिन शुभ हो।